tenders. Very shortly, the tenders will come. So, in all, instead of only ten procedures, we will have 66 procedures. In these 66 procedures, I am sure, most of the requirements as far as the dental care is concerned will come into being.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी टीथ वगैरह के बारे में बताया गया है, उसी तरह से आई लेंस की कीमत भी "**एम्स**" वगैरह में बहुत कम लगाई गई है, क्या इन सबको दोबारा review करने की कोशिश करेंगे? यह बात ठीक है कि CGHS बहुत अच्छा काम रहा है, लेकिन यह कुछ ही प्रदेशों में है, जैसे हिमाचल प्रदेश में CGHS की सुविधा नहीं है। जब कि वहां इतने exservicemen रहते हैं। क्या वहां CGHS खोली जाएगी, ताकि जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको भी इसकी सुविधा मिल सके?

SHRI DINESH TRIVEDI: Mr. Chairman, Sir, there is a continuous process of review. So, there is no particular reason to review a particular thing at this point in time. Sir, review or addition is an on-going process.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, मैंने दूसरा सवाल हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा था, उसका जवाब नहीं आया ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: No, no. One question please.

डा. सी.पी. ठाकुर : सर, यह जो बच्चों का irregular teeth का प्रोब्लेम है, यह इतना कॉमन हो गया है कि इसको disease में लेना चाहिए। चूंकि हमारा chewing habit बदल गया है, soft चीज खाते-खाते खाने का habit बदल गया है, इसलिए हमारा jaw छोटा हो गया है। आज सभी बच्चों को teeth में कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस पर कोई Technical Committee वगैरह बनाकर इसको consider किया जाए?

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, the hon. Member is not only a doctor but was also the ex-Health Minister, and we would welcome his suggestions to improve the entire dental care.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में CGHS के चार जोन हैं, जिनमें मात्र दो डेंटिस्ट उपलब्ध हैं, जब कि इसके अंतर्गत 90 डिस्पेंसरीज हैं। क्या दो डेंटिस्ट चार जोन के सभी patient को attend कर पाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि क्या डेंटिस्टों की संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है?

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, at the moment, there are no such schemes. But, if there is a particular place where the hon. Member feels that there are more patients than doctors, then, we are always open to such suggestions and comments, and we certainly would like to look into the matter.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, चार जोन में दो ही डेंटिस्ट हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपका सवाल हो गया है।

Recommendations of State Governments for NREGS

*362. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Mohsina Kidwai..

(a) whether several State Governments have recently give their recommendations on the objectives of the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the recommendations given by various State Governments have been examined by the Central Government; and

(d) if so, the details of the recommendations accepted by the Central Government and the manner in which those recommendations are likely to be implemented across the country?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C.P. JOSHI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. No State Government has recently given its recommendations on the objectives of NREGA.

(c) and (d) The recommendations given by the various State Governments for expansion of the works under NREGA have been considered by the Ministry of Rural Development. The benefits of works on individual lands as given in para 1(iv) of Schedule I of NREG Act have been extended to small and marginal farmers *vide* Notification dated 22.7.2009 as per the following amendment:

> "Provision of irrigation facility, horticulture Plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debit Relief Scheme, 2008."

Further, construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Village Knowledge Resource Centre and Gram Panchayat Bhawan at Gram Panchayat level has been included as a permissible activity in para 1 of Schedule I of the Act *vide* Notification dated 11.11.2009.

Other recommendations made in this regard are under consideration of the Government.

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति महोदय, आजादी के बाद हिन्दुस्तान में रुरल डेवलपेंट के लिए काफी काम हुए, क्योंकि 70 फीसदी आबादी गांव से ताल्लुक रखती है। इस वक्त "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के तहत इतना बड़ा काम हो रहा है, इसमें लगभग चार करोड़ से ज्यादा households आते हैं। इसमें जो important components हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे रुरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास हैं। अब जो माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं, वह बहुत अच्छी सोच है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ coordinate करें। उसको भी लेकर जितनी rural development की स्कीमें चल रही हैं, उनमें से जितनी भी देहात से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, बालवाड़ी हो, आंगनवाड़ी हो, school buildings हों, उन सबको इसमें लिया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे duplication भी रुकेगा और काम भी अच्छा होगा, लेकिन इसमें जो दो-तीन बहुत important components हैं, एक तो cooperation of the State

Governments, coordination, cooperation on monitoring, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस स्कीम के तहत कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने expansion मांगा और आपने नरेगा के तहत कुछ फील्ड्ज़ में उनको expand करने की इजाज़त भी दी है। इस वक्त दुनिया में हमारा वाहिद मुल्क है, जहां रूरल रीकंस्ट्रक्शन मिशन इतने ज़ोरदार तरीके से काम कर रहा है और सबसे बड़ी स्कीम हमारे देश में है। महोदय, इतनी बड़ी स्कीम के लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और बहुत मज़बूती के साथ monitoring की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उसके लिए इनकी मिनिस्ट्री का क्या प्लान है?

†[**محترمہ محسنہ قدوائی** : سبھا پتی مہودے، آزادی کے بعد ہندوستان میں رورل ڈیولپمنٹ کے لئے کافی کام ہوئے، کیوں کہ 70 فیصدی آبادی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت "راشٹریہ گرامین روزگار گارنٹی یوجنا" کے تحت اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس میں لگ بھگ چار کروڑ سے زیادہ ہاؤس۔ہولڈس آتے ہیں۔ اس میں جو important components ہیں، وہ اسٹیٹ گوورنمنٹس اور ہمارے رورل ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہیں۔ اب جو مانئے منتری جی سوچ رہے ہیں، وہ بہت اچھی سوچ ہے کہ دوسری منسٹریز کے ساتھ کو۔آرڈنیٹ کریں۔ اس کو بھی لے کر جتنی رورل ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں چل رہی ہیں، ان میں سے جتنی بھی دیہات سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ پردھان منتری سڑک یوجنا ہو، بالواڑی ہو، آنگن واڑی ہو، اسکول بلڈنگس ہوں، ان سب کو اس میں لیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے duplication بھی رہے گا اور کام بھی اچھا ہوگا، لیکن اس میں جو دو۔تین بہت important components ہیں، ایک cooperation of the State Governments, coordination, cooperation on monitoring, تو میں مانئے منتری جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس اسکیم کے تحت کچھ اسٹیٹ گوورنمنٹس نے expansion مانگا اور آپ نے نریگا کے تحت کچھ فیلڈز میں ان کو expand کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہمارا واحد ملک ہے، جہاں رورل ری۔کنسٹرکشن مشن اتنے زوردار طریقے سے کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی اسکیم ہمارے دیش میں ہے۔ مہودے، اتنی بڑی اسکیم کے لئے کو۔آرڈنیشن، کو۔آپریشن اور بہت مضبوطی کے ساتھ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے میں مانئے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے لئے ان کی منسٹری کا کیا پلان ہے؟]

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस स्कीम को लागू करने में सहयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसको address करने के लिए भारत सरकार ने उनको कुछ निर्देश दिया है कि लोकपाल का concept अपने स्टेट्स में लागू करें और सारे स्टेट्स से हमने रिक्वेस्ट की है कि लोकपाल के जो नियम हमने बनाए हैं, उनको ठीक ढंग से लागू करें।

जहां तक UCs हम लेते हैं, उसमें भी हमने उनसे कहा है कि वहां पर हमें पूरी जानकारी दें कि fund utilisation किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वहां implementation में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। हमने MIS develop किया है, इस MIS के माध्यम से हम जानकारी लेकर उनको समय-समय पर directions देने का काम कर रहे हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स को समय-समय पर यह निर्देश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस स्कीम को ठीक ढंग से लागू करने के लिए पंचायत को ज्यादा activate करें। इस Act में यह प्रोविज़न किया गया है कि वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति और ज़िला परिषद को स्वयं अपनी योजना बनानी है और योजना बनाकर उसको लागू करना है। इसलिए हम सरकारों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि नरेगा के माध्यम से लागू करने के लिए जो Panchayat Act में प्रोविज़न किए गए हैं, उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करें और स्टेट गवर्नमेंट्स खुद अपना redressal mechanism develop करें। सोशल ऑडिट का concept हमने लागू किया है और पंचायतों को अधिकार दिया है कि सोशल ऑडिट करें। इस ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के कोऑपरेशन के साथ इस योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित कर सकें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि जो अखबारात में आता है और आपके बयानात भी आते हैं कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा खर्च नहीं कर रही हैं और बड़े ताज्जुब की बात है कि वे स्टेट्स, जहां गरीबी बहुत है, जैसे बिहार, यू.पी., वहां सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है। आपने तीन साल में आपने बहुत काम किया है, लेकिन आपने कोई evaluation कराया है? तीन साल के अंदर आपको क्या कमियां नज़र आईं? जैसे आपका जो फंड जाता है, उसमें administration पर कितना खर्च होता है और wages पर कितना खर्च होता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, जिनको evaluate करना चाहिए। मेरा सवाल एक और है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 50 परसेंट महिलाएं इसमें भाग लेती हैं और उनको wages दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अब 4 करोड़ से ज्यादा households इसमें हैं। दूसरी तरफ आपके Self Help Groups भी काम कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर काम में बहुत potentiality है, काम किया जा सकता है, तो ये जो हमारी 50 परसेंट महिलाएं काम कर रही हैं और जो Self Help Groups हैं, इनको बहुत ही gradually wage employment से self employment की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस सिलसिले में आपकी कोई प्लानिंग है कि इस wage employment को self employment में बदल दिया जाए?

†[**محترمہ محسنہ قدوائی** : سر، میرا دوسرا سپلیمنٹری کوئشچن یہ ہے کہ جو اخبارات میں آتا ہے اور آپ کے بیانات بھی آتے ہیں کہ بہت سی اسٹیٹ گوورنمنٹس پیسہ خرچ نہیں کر رہی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ اسٹیٹس، جہاں غریبی بہت ہے، جیسے بہار، یو پی۔، وہاں سب سے کم پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ نے تین سال میں آپ کے بہت کام کیا ہے، لیکن آپ نے کوئی evaluation کرایا ہے؟ تین سال کے اندر آپ کو کیا کمیاں نظر آئیں؟ جیسے آپ کا جو فنڈ جاتا ہے، اس میں administration پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور wages پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جن کو evaluate کرنا چاہئے۔ میرا سوال ایک اور ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری 50

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

فیصد مہیلائیں اس میں بھاگ لیتی ہیں اور ان کو wages دئے جاتے ہیں۔ میں مانئے منتری جی سے
کہنا چاہتی ہوں کہ اب 4 کروڑ سے زیادہ ہاؤس ہولڈ اس میں ہیں۔ دوسری طرف آپ کے Self Help
Groups بھی کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر کام میں بہت employment potentiality کی
طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں مانئے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی
کوئی پلاننگ ہے کہ اس wage employment کو self employment میں بدل دیا جائے۔

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, इस Act के Objective में यह बात लिखी हुई है कि हम यह assure कर रहे हैं कि उनको unskilled manual work के लिए 100 days का काम देंगे। इसलिए जहां तक यह बात है कि उनको skill के साथ या wage employment के साथ जोड़ें, इस Act की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस demand-driven scheme में हमने यह प्रोविज़न किया है कि हम assure करते हैं कि 100 days का manual work आपको देंगे। अब उनको आकर काम लेना है, पंचायत में application देनी है, उसके बाद हम काम देते हैं। इसलिए हम इसको wage के साथ तभी लिंक कर सकते हैं, जब काम करने वाले लोग इसके साथ आएं, लेकिन सभापति महोदय, एक बात बिल्कुल सही है कि 2008-09 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, केवल मात्र 14 परसेंट ऐसे लोग हैं, जो 100 days का काम कर रहे हैं। इसका मतलब 15 करोड़ लोग eligible हैं, उसमें से 14 परसेंट लोग काम कर रहे हैं। यह इस बात को indicate करता है कि हमारे पास रूरल इलाके में 14 परसेंट लोग ही manual work में काम करना चाहते हैं। बाकी लोग मैन्युअल वर्क में काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए gradualy इस मैन्युअल वर्क को unskilled के अंदर हम include करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसको करेंगे। अभी हम इसको ठीक ढंग से इवैल्युएट कर रहे हैं। जितना हमने स्कोप बढ़ाया है, उतना in-put लेने के बाद हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।

SHRI M. RAMA JOIS: Mr. Chairman, Sir, as a result of want of employment and sufficient income, and basic amenities people from many villages are migrating to the urban areas. It is adversely affecting agriculture and also sustenance and development of village industries. What steps are being taken to prevent migration of the people from villages to urban areas?

SHRI C. P. JOSHI: The Scheme has already given them opportunities for not moving from the rural areas to the urban areas. So, this is the Scheme where these people are not going to the urban areas. They are staying in the rural areas. In fact, we are addressing the question which you have asked.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I want to know from the hon. Minister this. The Ministry, the Government, is committed to implementing daily wages of Rs.100. We raised this question last time also. We didn't receive any reply. This is a specific question. There are other problems. I know that in the case of West Bengal Government there is a due of Rs.700 crores. The Ministry has not released that. But the specific question is this. When will this daily wages of Rs.100 be implemented?

SHRI C.P. JOSHI: Sir, we have already issued instructions. From 1st April we have introduced it and they will be eligible for Rs.100. That notification has already been issued. *(Interruptions)*... It is from 1st April, 2009. *(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।

SHRI C.P. JOSHI: Sir, we have already issued the notification saying that they will be paid from 1st April, 2009. Rupees Hundred will be given to all those States who have recommended Rs.100. There are a few States which have not recommended up to Rs.100. One of the States is West Bengal. They have not requested for Rs.100. *(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, that is very wrong. You have not released the earlier request from West Bengal Government. If you recall, in January, they have made a request. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, you can't ask supplementaries like this. *(Interruptions)*... Mrs. Karat, please resume your seat. *(Interruptions)*... This is not your question. *(Interruptions)*... This is not your question. *(Interruptions)*... Mrs. Karat, I am sorry. *(Interruptions)*... I am sorry that there will be no interventions when supplementaries are being asked. *(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: They want to pay Rs.87. We are ready to pay Rs.100. *(Interruptions)*... Therefore, we are saying it. *(Interruptions)*... Till today the West Bengal Government did not demand Rs.100. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mrs. Karat, this is not your question. *(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: Till today the West Bengal Government demanded only Rs.87. We are ready to pay Rs.100. *(Interruptions)*... You are not paying Rs.100. That is the issue. *(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: That was earlier. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the answer is incorrect, there are procedures for pointing out that. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल : धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो scope of work खुदाई से और कौन-कौन क्षेत्रों में चला गया है ? इसके scope of work का विवरण इसमें विस्तार नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि एक जवाहर रोजगार योजना होती थी, जो राजीव गांधी जी के जमाने में लांच की गई थी और वह बहुत सफल रही थी। वह जवाहर रोजगार योजना कहां पर है, “नरेगा” की वजह से उसकी कहीं पर चर्चा नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जवाहर रोजगार योजना का विलय “नरेगा” में कर दिया गया है या यह योजना अभी है ? अगर है, तो कितना पैसा जवाहर रोजगार योजना के लिए स्वीकृत होता है ?

श्री सी0पी0 जोशी : सभापति महोदय, यह अलग से प्रश्न है। फिर भी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि नेशनल रूरल एम्पलाईमेंट स्कीम के अंतर्गत वह योजना समाहित हो गई है।

Mandatory Reporting of Large Case Transactions by Banks

*363. SHRI S.S. AHLUWALIA:††
SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri S.S. Ahluwalia.